



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 17 फरवरी, 2001/28 माघ, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जनवरी, 2001

संख्या ई० एक्स० एन०-बी०(1)-1/98.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 14-12-1999 को जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित, सरकार की अधिसूचना संख्या ई० एक्स० एन०-बी० (1)-1/98, तारीख 7-12-1999 द्वारा जारी, हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिकरण (पीठासीन अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) निम्न, 1999 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं।

इन नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति, इन नियमों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप करना व सुझाव देना चाहे तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, लिखित रूप में आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को भेज

मकेगा । उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, पर, सरकार द्वारा इन्हें अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाए, अर्थात् :—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिकरण (पीठासीन अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियम, 2001 है ।

(ii) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 4 का संशोधन—हिमाचल प्रदेश साधारण विक्रय कर अधिकरण (पीठासीन अधिकारियों को वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 4 में,—

(क) उप-नियम (1) में शब्दों “आयुक्त एवं सचिव” के स्थान पर “वित्तायुक्त एवं सचिव” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-नियम (5) में शब्दों “आयुक्त एवं सचिव” के स्थान पर “वित्तायुक्त एवं सचिव के 22400—24400 रुपए” शब्द और ग्रंथ प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

3. नियम 5 का प्रतिस्थापन—उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“5. पेंशन.—(1) अधिकरण के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा :

परन्तु उसे ऐसी पेंशन संदेय नहीं होगी, यदि उसने अधिकरण में दो वर्ष से कम अवधि की सेवा की हो ।”

(2) उप-नियम (1) के अधीन पेंशन, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या इसके भाग के लिए, 700 रुपए प्रतिवर्ष की दर से संगणित की जाएगी और अधिकरण में सेवा वर्षों की संख्या को विचार में लाए बिना पेंशन की अधिकतम रकम प्रतिवर्ष 3500 रुपए होगी :

परन्तु यह कि अधिकरण में पदधारित करते समय प्राप्त या प्राप्ति के लिए हकदार पेंशन के संगणित भाग (यदि कोई हो) को शामिल करके किसी भी पेंशन की रकम सहित इस नियम के अधीन संदेय पेंशन की संकलित रकम, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विहित पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी ।”

4. नियम 10 का संशोधन—उक्त नियमों के नियम 10 में शब्दों “आयुक्त एवं सचिव” के स्थान पर “वित्तायुक्त एवं सचिव” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[Authoritative English text of this Department notification No. EXN-B (1) 1/98, dated 22-1-2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd January, 2001

No. EXN-B (1)-1/98.—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968 (Act No. 24 of 1968), the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh General Sales Tax Tribunal (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service of Presiding Officer) Rules, 1999 published in Rajpatra, Himachal Pradesh, Extra-Ordinary, dated 14th December, 1999 issued *vide* Government Notification No. EXN-B (1) 1/98, dated 7th December, 1999 for the general information of the public.

If any person likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s) to make in relation to the proposed rules, he may send the same in writing to the Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171009, within a period of 30 days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

The objection(s)/suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalising the same, namely:—

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh General Sales Tax Tribunal (Salaries, Allowances and Other Condition of Service of Presiding Officer) Amendment Rules, 2001.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Rule 4.—In Rule 4 of the Himachal Pradesh Sales Tax Tribunal (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service of Presiding Officer) Rules, 1999 (hereinafter referred to), the said rules.—

(a) In sub-rule (1) for the words “Commissioner-cum-Secretary”, the words “Financial Commissioner-cum-Secretary” shall be substituted; and

(b) In sub-rule (5) for the words “Commissioner-cum-Secretary”, the words and figures “Rs. 22400—24400 of Financial Commissioner-cum-Secretary” shall be substituted.

3. Substitution of Rule 5.—For Rule 5 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

“5. Pension.—(1) Every pension appointed to the Tribunal as the Presiding Officer, shall be entitled to pension:

Provided that no such pension shall be payable if he has put in less than two years of service with the Tribunal.

- (2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed year of service or a part thereof and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum amount of pension shall not exceed rupees three thousand five hundred per annum.

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension (if any), drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court."

4. *Amendment of Rule 10.*—In Rule 10 of the said rules, for the words "Commissioner-cum-Secretary" the Words "Financial Commissioner-cum-Secretary" shall be substituted.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-Secretary.